



2026:AHC:26361-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) सं. - 3564 सन् 2025

दलीप सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 13 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : संजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से लोक नाथ शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : ए.के. गोयल (ए.सी.एस.सी.)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को आगरा जिले के तहसील खैरगढ़ तहसील बेरी चाहर गांव में स्थित खसरा संख्या 246 ए से 0.0580 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
2. प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन भूमि को नाले (नाला) के रूप में दर्ज किया गया है, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 7 से 14 ने उक्त नाले पर अतिक्रमण किया है और इस संबंध में बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि खसरा संख्या 246 ए में शामिल भूमि निजी पक्षकारों के स्वामित्व में है, जबकि खसरा नंबर 246 बी नाली है और उक्त नाले पर कोई अतिक्रमण नहीं है। खसरा नंबर 246ए से संबंधित याचिका निराधार है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि खसरा नंबर 246 ए को नाली (नाला) के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड के विपरीत है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर दस्तावेज़ (अनुलग्नक-5) के अवलोकन से पता चलता है कि खसरा नंबर 246/2 में, जिसे नाला के रूप में दर्ज किया गया है, इंगित क्षेत्र 0.265 है और दस्तावेज़ (अनुलग्नक-6) में, इसे खसरा नंबर 246बी के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 0.2650 है।
5. एक बार जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि नाला के रूप में दर्ज भूमि 246बी/246/2 है, तो यह दावा कि खसरा नंबर 246ए में शामिल भूमि नाला की है, जाहिरा तौर पर, निराधार है।
6. हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली)

फरवरी 6, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"